THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) While no instructions were issued to the State Governments in regard to amendments in the Sales Tax, Octroi, market fee etc., letters were addressed to all Chief Ministers/Administrators of the States suggesting *inter alia* to consider such measures as reduction of sales tax/octroi and suitable incentives for attracting more private sector investment in the respective States. As per the information available in the Ministry, State Governments of West Bengal, Haryana, Karnataka and Maharashtra have responded to the suggestion of the Central Governmennt and have provided several incentives for setting up of food processing industries.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना

1034. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितने-कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किए गए हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से या निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1992 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंकस्रण एककों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मध्य प्रदेश में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान इन एककों को केंद्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गयी है ; और

(ङ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ.) यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित सभी खाद्य प्रसंकरण उद्योगों के संबंध में राज्यवार सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती फिर भी चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, मछली प्रसंस्करण यूनिटों, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और खाद्य उत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत मृदुवातित पेय यूनिटों की संख्या विवरण में दी गई है (**नीचे देखिए**)। मध्य प्रदेश में फलउत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत 72 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 27 वातित फल यूनिट, 3674 चावल मिलें और 25 रोलर आटा मिलें हैं। यह मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता परंतु ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने राज्य संगठनों/सहकारिता संयुक्त सेक्टर/सहायित सेक्टर के यूनिटों को सहायता देनेहेतु स्कीमें तैयार की है। होशंगाबाद जिले में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी के रूप में मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल को वर्ष 1990-91 के दौरान 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। भोपाल में पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम लिमिटेड, भोपाल से भी प्राप्त हुआ था और 1991-92 के दौरान इक्विटी के रुप में 62.5 लाख रुपए और ऋण के रूप में 25 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। होशंगाबाद जिले में बाबई स्थान में खुम्भी उत्पादन और प्रसंकस्रण के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु अनुदान सहायता के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल से भी 1991-92 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा दुर्ग में टमाटर पेस्ट, आम सांप्रण आदि तैयार करने के लिए 100%

निर्यातोन्मुखी यूनिट की स्थापना के एक प्रस्ताव को भी 1990–91 में मंजूरी दी गई है । पेय एल्कोहल तैयार करने के लिए 54 आवेदन-पत्र और बीयर तैयार करने के लिए 89 आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए थे जिनमें से पेय एल्कोहल और बीयर प्रत्येक के लिए दो-दो आशय जारी किए गए हैं और बाकी प्रस्तावों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

विवरण

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और मृदु वातित पेय यूनिटों (31–1–1992 को) की संख्या

	राज्य का नाम	फल एवं सब्जी यूनिट	मृदु वातित पेय यूनिट
1.	आन्ध्र प्रदेश	201	—
2.	असम	19	—
3.	बिहार	43	10
4.	गुजरात	171	52
5.	हरियाणा	115	17
6.	हिमाचल प्रदेश	70	1
7.	जम्मू और कश्मीर	68	6
8.	कर्नाटक	176	38
9.	केरल	259	24
10.	मध्य प्रदेश	82	27
11.	महाराष्ट्र	506	85
12.	मणिपुर	11	1
13.	मेघालय	7	1
14.	नागालैंड	4	—
15.	उड़ीसा	17	4
16.	पंजाब	158	9
17.	राजस्थान	78	24
18.	सिक्किम	2	—
19.	तमिलनाडु	314	35
20.	त्रिपुरा	3	—

राज्य का नाम	फल एवं सब्जी यूनिट	मृदु क्षानित पेय यूनिट
21. उत्तर प्रदेश	379	39
2. पश्चिम बंगाल	214	23
23. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	—
24. अरुणाचल प्रदेश	2	—
25. चंडीगढ़	24	7
26. दादर और नगर हवेली	5	2
27. दिल्ली	151	18
28. गोवा	131	86
29. मिजोरम	2	—
30. पांडिचेरी	9	2
योग :	3222	577

(2) मछली प्रसंस्करण यूनिट (31-12-1991 को)

राज्य का नाम	यूनिट संख्या
केरल	103
कर्नाटक	19
लक्षद्वीप	1
तमिलनाडु	31
महाराष्ट्र	41
गुजरात	28
गोवा	5
आन्ध्र प्रदेश	26
पश्चिम बंगाल	30
उड़ीसा	15
	299

इसके अलावा 131 बर्फ बनाने वाले यूनिट और 330 शीत भण्डार है ।

(3) 1-1-1992 को चावल मिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	हलर्स	शेलर्स	हलर्स एवं शेलर्स	आधुनिक/ आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	305	14	1871	418	2608
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	1	222	1115
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13413	2	13	2668	16096
10.	मणिपुर	71	—	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	6191	99	472	2515	9277
12.	मध्य प्रदेश	3114	239	227	94	3674
13.	मेघालय	85	—	8	—	93
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	17
19.	तमिलनाडु	13292	144	1530	3262	18228
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9404	2	71	980	10457
23.	चंडीगढ़	4	—	—	27	31
24.	दिल्ली	3	—	—	31	34
25.	पांडिचेरी	179	—	8	33	220

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	हलर्स	शेलर्स	हलर्स एवं शेलर्स	आधुनिक/ आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
26.	अंडमान और निकोबार	116	—	—	—	116
27.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
28.	दादर और नागर हवेली	8	1	—	—	9
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	गोवा	675	—	5	37	717
31.	मिजोरम	—	—	—	—	—
		86315	4098	8300	32969	131682

(i) 1-1-1992 को रोलर आटा मिलों की कुल संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आटा मिलों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	56
2.	असम	41
3.	बिहार	44
4.	चंडीगढ़	2
5.	दिल्ली	17
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	18
10.	कर्नाटक	54
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	25

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आटा मिलों की कुल संख्या
13	महाराष्ट्र	45
14	मणिपुर	1
15	उड़ीसा	21
16	पंजाब	16
17	पांडिचेरी	2
18	राजस्थान	5
19	तमिलनाडु	53
20	उत्तर प्रदेश	70
21	पश्चिम बंगाल	27
22	सिक्किम	1
23	गोवा	1
24	त्रिपुरा	2
	योग :	583

Joint venture deep sea fishing projects

1035. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether a large number of proposals are under Government's consideration for joint ventures in deep sea fishing and sea food business, involving fishing companies from the USA, Japan and Saudi Arabia; and

(b) if so, the details of the projects under consideration and the present state of negotiations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) There is no pending proposal under Government's consideration from fishing companies from the USA, Japan and Saudi Arabia.

(b) Does not arise.

Joint deep sea fishing projects with USSR

1036. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the joint fishing projects to be financed by India and the erstwhile Soviet Union, are in jeopardy due to recent developments in the Soviet Union; and

(b) if so, whether Government approached any other country for collaboration in deep sea fishing and the response to the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO: (a) No, Sir.

(b) Does not arise.